

पेज नंबर 1/5

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 111/2015

अपीलांत

- 1 पूनाराम पुत्र पुखजी भाट
- 2 पोलाराम पुत्र पुखजी भाट
- 3 पारस पुत्र पुखजी भाट
- 4 (1) राणाराम पुत्र मन्नारामजी
(2) मृतक भोमाराम पुत्र मन्नाराम जी के कायम मुकाम:-
 - 4/2/1 रमेश पुत्र भोमाराम उर्फ भवरलाल
 - 4/2/2 जगदीश पुत्र भोमाराम उर्फ भवरलाल
 - 4/2/3 तेजाराम पुत्र भोमाराम उर्फ भवरलाल
 - 4/2/4 मैना पुत्री भोमाराम उर्फ भवरलाल
 - 4/2/5 रानीया पत्नि भोमाराम उर्फ भवरलाल
- 5 देवाराम पुत्र रतनाजी भाट
- 6 मृतक कानाराम पुत्र खीमारामजी भाट के कायम मुकाम
 - 6/1 अशोक पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम जी,
 - 6/2 दिनेश पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम जी
 - 6/3 लीला पत्नि स्वर्गीय श्री कानाराम जी
- 7 ओकाराम पुत्र जीवाजी भाट
- 8 मृतक हेमाराम पुत्र हीराज भाट के कायम मुकाम
 - 8/1 लक्ष्मण पुत्र स्वर्गीय श्री हेमाराम जी
 - 8/2 मिटु पुत्र स्वर्गीय श्री हेमारामजी
 - 8/3 मदन पुत्र स्वर्गीय श्री हेमारामजी
 - 8/4 किशन पुत्र स्वर्गीय श्री हेमारामजी
 - 8/5 सतोंष पुत्री स्वर्गीय श्री हेमारामजी
- 9 पुखजी पुत्र प्रताजी भाट
- 10 मृत लादूराम पुत्र हजारीजी भाट के का मु
 - 10/1 मोहन पुत्र हजारीजी भाट
- 11 कानाराम पुत्र धनजी भाट
- 12 मृतक जीवाराम पुत्र हजारीजी भाट के का मु:-
 - 12/1 बाबुराम पुत्र जीवारामजी
 - 12/2 भंवर पुत्र जीवारामजी
- 13 बाबुलाल पुत्र रघुनाथजी भाट
- 14 भंवरलाल पुत्र ढलजी भाट
- 15 (1) मोतीराम पुत्र ओखारामजी
(2) सोहनराम पुत्र ओखारामजी
(3) छगनलाल पुत्र ओखारामजी
(4) श्रीमती गीता पत्नि ओखारामजी
- 16/1 सुआ देवी पत्नि हजारीजी,
- 16/2 नारायणलाल पुत्र हजारीजी,
- 16/3 चुन्नीलाल पुत्र हजारी जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली



पेज नंबर 2/5

16/4 हिम्मताराम पुत्र हजारीजी

16/5 रमेश पुत्र हजारीजी

16/6 छगन पुत्र हजारीजी

समस्त जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर, पाली, तहसील व जिला पाली
(राजस्थान)

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से



:- निर्णय :-

दिनांक : 20.05.2019.

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मैजा ग्राम भालेलाव पटवार क्षेत्र भांगेसर के खसरा नंबर 340/3 रकबा 208 बीघा 16 बिस्वा के संबध में पेश कर खातेदारी घोषणा का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा आवेदन आदेश 22 नियम 3 व 9 तथा आवेदन 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी का प्रस्तुत कर उक्त पक्षकारान के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब, बहस हेतु नियत थी, इसी दौरान राजस्व लोक अदालत व कैम्प कोर्ट में उक्त पत्रावली प्रस्तुत हुई, जहां पर बिना अपीलांटगण कोकायम मुकामात आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिये ही सीधे ही वादी संख्या 4(3) एवं वादी संख्या 10(1) और वादी संख्या 16 की मृत्यु पूर्व में होना बताकर निर्धारित समय में आवेदन पेश नहीं करने से अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एबेट हो जाने से खारिज कर दिया गया। अपीलांटगण अलग-अलग वादग्रस्त भूमि में हिस्से पर काश्त करते हैं और अलग-अलग निवास करते हैं। जिससे किसी भी अपीलांट की मृत्यु होने पर दूसरे अपीलांट को जानकारी होना संभव नहीं है। अपीलांट कम पढे-लिखे, अनपढ केवल मात्र साक्षर हैं, साथ ही मजदूर खेतीहर व्यक्ति हैं, जिन्हे कानून की कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जानकारी नहीं है ऐसी स्थिति में कायम मुकाम रेकॉर्ड पर लाये जाने बाबत आवेदन हेतु समय दिया जाना आवश्यक था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल राज्य सरकार की मंशा अनुरूप अधिकतम प्रकरणों को निर्णीत करने के उद्देश्य से विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मैजा ग्राम भालेलाव पटवार क्षेत्र भांगेसर के खसरा नंबर 340/3 रकबा 208 बीघा 16 बिस्वा के संबंध में पेश कर खातेदारी घोषणा का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा आवेदन आदेश 22 नियम 3 व 9 तथा आवेदन 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर उक्त पक्षकारान के कायम मुकाम को रेकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया। किन्तु अपीलांटगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 90 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद एबेट होने का हवाला देते हुए खारिज किया गया। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मैजा ग्राम भालेलाव पटवार क्षेत्र भांगेसर के खसरा नंबर 340/3 रकबा 208 बीघा 16 बिस्वा के संबंध में पेश कर खातेदारी घोषणा का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद कायम मुकाम रेकॉर्ड पर लेने से संबंधित प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने से वाद एबेट होने का हवाला देते हुए खारिज किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर०आर०टी० 2005 (2) पेज 929 में यह प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश 22 नियम 3 वादी के विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन - अपीलांट के पिता ने वाद पेश किया, किन्तु अपील के विचाराधीन होने के तथ्य से अपीलांट अनभिज्ञ था - एडवोकेट के पत्र से अपीलांट की जानकारी में तथ्य आया - कालबाधित होने से आवेदन खारिज किया गया तथा उपशमन अपास्त करने व विलम्ब माफ करने का अनुतोष नहीं चाहा-तकनीकी आपत्तियां रास्ते में नहीं आनी चाहिये - आदेश अपास्त किया तथा विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया। इसी प्रकार एस०सी०आर० 2010 (8) पेज 597 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Code of Civil Procedure, 1908 - Order 22, rules 3 and 9; s. 151 read with s.5 of Limitation Act, 1963 - Death of appellant during pendency of appeal before Supreme Court - Application filed after long delay of 778 days for bringing the legal representatives of deceased appellant on record accompanied by application for condonation of delay - Held: Such applications cannot be allowed as a

matter of right and even in a routine manner – They should be rejected unless sufficient cause is shown for condensation of delay – On facts, except for a vague averment that the legal representatives were not aware of the pendency of the appeal, no other justifiable reason was stated by the applicants – The applications also did not contain correct and true facts, thus, want of bona fides is imputable to the applicants – No reason nor sufficient cause was shown as to why immediate steps were not taken by the applicants, even after they admittedly came to know of the pendency of the appeal – The conduct of the applicants was abnormal – They acted irresponsibly and even with negligence, and miserably failed in showing any 'sufficient cause' for condonation of the long delay of 778 days – Applications accordingly dismissed – Resultantly, the appeal, having already abated, also dismissed. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रामनाथ साआ एल्यास रामनाथ साओ एण्ड अदर्स बनाम गोवर्धन साओ एण्ड अदर्स (2002)3 एस.सी.सी. पेज 195 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The expression "sufficient cause" within the meaning of Section 5 of the Act or Order 22 Rule 9 of the Code or any other similar provision should receive a liberal construction so as to advance substantial justice when no negligence or inaction or want of bona fide is imputable to a party. In a particular case whether explanation furnished would constitute "sufficient cause" or not will be dependent upon facts of each case. There cannot be a straitjacket formula for accepting or rejecting explanation furnished for the delay caused in taking steps. But one thing is clear that the courts should not proceed with the tendency of finding fault with the cause shown and reject the petition by a slipshod order in over jubilation of disposal drive. Acceptance of explanation furnished should be the rule and refusal an exception more so when no negligence or inaction or want of bona fide can be imputed to the defaulting party. On the other hand, while considering the matter the courts should not lose sight of the fact that by not taking steps within the time prescribed a valuable right has accrued to the other party which should not be lightly defeated by condoning delay in a routine like manner. However, by taking a pedantic and hyper technical view of the matter the explanation furnished should not be rejected when stakes are high and/or arguable points of facts and law are involved in the case, causing enormous loss and irreparable injury to the party against whom the lis terminates either by default or inaction and defeating valuable right of such a party to have the decision on merit. While considering the matter, courts have to strike a balance between resultant effect of the order it is going to pass upon the parties either way." इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज नंबर 5/5

885 में यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय की गलती के लिये पक्षकार पीड़ित नहीं हो सकता—विचारण न्यायालय ने बहुत ही अधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया—निर्णीत, आवेदन स्वीकार किया और विधिक वारिशान को रेकार्ड पर लिया जावे।" इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये — तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद केवल मात्र कायम मुकाम का आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने से खारिज किया गया। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों के कायम मुकाम पर रेकार्ड पर लिये जाकर उभयपक्षों का सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड लौटाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशासम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली